



# भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वॉटर ट्रीटी को रद्द किया

**भारत के विदेश मंत्रालय ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्युरिटी की बैठक में हुए इस अहम फैसले की जानकारी दी**

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 अप्रैल। भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वॉटर ट्रीटी (आई.डब्ल्यू.टी.) को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है और पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियाँ खत्म होने तक यह करार रहेगा। इसी के साथ कई अन्य कदम भी उठाए गए हैं, जिनमें वारा-अटारी चैक पोस्ट बंद करने। पाकिस्तानीयों का वीसा रद्द करना आदि शामिल है।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसे कथित रूप से पाकिस्तान के आतंकी गटों ने अंजाम दिया है, के बाद से भारत के सामरिक एवं राजनीतिक हलकों में इंडस वॉटर ट्रीटी रद्द करने की मांग जोर-शोर से उठी थी।

- पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत के सामरिक एवं राजनीतिक हलकों में इंडस वॉटर ट्रीटी रद्द करने की मांग जोर-शोर से उठी थी।
- इस संधि के तहत पूर्वी भाग की रावी व्यास और सतलुज नदियों पर भारत का नियंत्रण है, तो सिंधु, झेलम और चिनाब पर पाकिस्तान का नियंत्रण है।
- पाकिस्तान का अस्तित्व एक तरह से इस संधि पर निर्भर है। पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था इसी के सहारे जीवित है।
- गैरतलब है कि 1960 में विश्व बैंक ने भारत व पाकिस्तान के बीच यह संधि करवाई थी और यह दो परस्पर विरोधी पड़ोसी देशों के बीच सहयोग का दुर्लभ उदाहरण मानी जाती रही है। तीन युद्धों व दशकों से पाकिस्तान द्वारा भारत में किए जा रहे आतंकी हमलों के बावजूद यह संधि कायम रही।

सुनियोजित साजिश रच कर किया गया घोषित कर देना चाहिए और जिज्ञासन ये क्षुर कृत्य बताया। उठोने भारत सकता है, जिसके आतंकी हमले में भारत की ही जीमीन पर 28 लोग मारे गए हैं।

वरिष्ठ बकील एवं राज्यसभा संसद कपिल सिंबल ने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इसे एक

की नायाब मिसाल माना जाता है। सबाल यह नहीं है कि संधि को निलमित किया जाना चाहिए, बल्कि यह है कि क्या ऐसा करना सार्थक और रणनीतिक रूप से बुझिमानी भी कर्म होगा।

तीन बड़े युद्धों के बाद भी कई दशकों की शत्रुओं के बाद भी यह साधा कायम रही, क्योंकि दोनों देशों की जल सुक्ष्मा सुनियोजित करने में इसकी अमीनी बोधिका है। इसके तहत रावी, व्यास और सतलुज जैसे पूर्वी नदियों पर भारत का नियंत्रण है और सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी परिस्थितों का नियंत्रण पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, भारत को इन नदियों के पानी के सीमित उपयोग की अनुमति है।

कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, अगर भारत ने एक दरकारी नियंत्रण कर देता तो विश्वास भारत को पालन करने वाले कानून परस्पर देश के रूप में सहित, उत्की मित्र मंडलों के करीब 32 लोग अपने बच्चों सहित पहलगाम के एक होटल में दर्शकों के साथ हैं। अतंकी हमले के दौरान भी वे होटल के बाहर रहे थे और विश्व बैंक ने यह भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलमित करने से भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## जैसलमेर के 32 लोग पहलगाम में फंसे

जैसलमेर, 23 अप्रैल (नि.स.)। जैसलमेर से कश्मीर बैंडों गए बड़ी संख्या में सैलानी आपने परिवार के साथ पहलगाम के होटल में फंसे हैं। पहलगाम प्रशासन द्वारा सभी होटल संचालकों को जाल लगाया आतंकी आदेशों तक किसी भी सैलानी को होटल से चेकआउट करने पर अंतिम रोक लगाई है, इसके कारण ये सैलानी होटल में ही

- प्रशासन ने अगले आदेशों तक सभी होटल संचालकों को किसी भी सैलानी को "चेकआउट" नहीं करने देने के लिये कहा है।

रुकने को मजबूर है। जैसलमेर में व्यापार करने वाले विपुल भाइयों पर विमल भाइयों ने एक दरकारी नियंत्रण कर देता तो विपुल भाइयों का पालन करने वाले कानून परस्पर देश के रूप में सहित भारत की छाँकी को भारी धक्का लगेगा और क्षेत्रीय जल विवाद में गतल मिसाल बनेगा।

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलमित करने से भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका पूरा सहयोग देगा-उपराष्ट्रपति वैंस

नवी दिल्ली, 23 अप्रैल। भारत की यात्रा पर आये अमेरिका के उपराष्ट्रपति जैदी वैंस ने आज प्रधानमंत्री नेत्रें मोदी से और पहलगाम में हुए नृपतंश आतंकवादी को लेकर एक विश्वसनीय मत्तु नियंत्रण करने के लिए जोर देते हुए कहा।

सिंबल ने कहा कि पाकिस्तान को औपचारिक रूप से आतंकवादी राष्ट्र शुरू पड़ासी राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग के लिये व्यापक दृष्टिकोण से विवादों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। आई.डब्ल्यू.टी. पर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे और विश्व बैंक ने यह भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलमित करने से भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलमित करने से भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलमित करने से भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलमित करने से भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलमित करने से भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलमित करने से भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलमित करने से भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलमित करने से भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलमित करने से भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलमित करने से भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलमित करने से भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलमित करने से भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलमित करने से भारत को कोई तकलीक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उत्पादक प्रबाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ विश

## विचार बिन्दु

मन जिस रूप की कल्पना करता है वैसा हो जाता है, आज जैसा वह है वैसे उसने कल कल्पना की थी। -योगविश्लेषण

## राजस्थान : सौर ऊर्जा का हब और भीषण गर्मी में बिजली की मारक कटौती

### रा

जस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल एक ओर जैसलमेर जिले में सौर ऊर्जा के एक बड़े निजी पार्क का उद्घाटन कर रहे थे और ठीक उसी समय राज्य के बिजली मन्त्री पोकरण में बिजली कटौती की शिकायत पर एक इन्जिनियर को सस्पेंड कर रहे थे, मानो इन्जिनियर महोदय बिजली के उत्पादक हों। इसे कहते हैं बिजली के घर में अंधेरा जो राजस्थान, भारत का सौर ऊर्जा का गढ़, 2025 में अपनी चमकती सौर परियोजनाओं और 24,102 मेंगावट की स्थापित क्षमता के साथ देश में अचूक है, उसी राज्य में बेहतरीन बिजली कटौती हो रही है चन्द्र गिरे-चुने बड़े शहरों को छोड़ देते तो अधिकांश कन्फ्यूं और ग्रामीण इलाकों की हालत खराब है जिसमें गर्मी का अधीन तो बस अरक्षण है और लोग बेहाल हैं।

केंद्रीय विद्युत प्रशिक्षण के मुताबिक, अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक राज्य ने 11,859.51 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया, जिसमें सौर ऊर्जा का योद्धान 43,572.46 मिलियन यूनिट रहा। यह आंकड़ा राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2023 और एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 की सफलता का प्रतीक तो ही ही, जो 2030 तक 90 गिरावट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखती है। भादला सौर पार्क जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स ने निश्चय ही राजस्थान के विविध सौर ऊर्जा नवाचेर पर ला खड़ा किया है। लेकिन इस समक्ष के पीछे एक अंधेरा सच छिपा है- बिजली कटौती, नए कठिनाइयों के लिए गरमारी, डिस्कॉम का भारी चाटा, उभोक्ताओं को महंगी बिजली की सलाई, किसानों के लिए रात में बिजली अपूर्णत की अमानवीय व्यवस्था, और सौर परियोजनाओं में व्यापक ग्रामीण इलाकों का आपान बाहरा सौर ऊर्जा ने राजस्थान को आपाननंद बनाने का सुनहरा सपना दिखाया है।

राज्य की 29,858 मेगावाट की कुल सौर कीरणी ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक है। कुसुम योजना, रूफटॉप सौर प्रणालियां, और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की पहुंच बढ़ाई है। 2025 तक, 13 मिलियन से अधिक उपभोक्ता डिस्कॉम के नेटवर्क से जुड़े हैं, जो कुल ऊर्जा खपत का 30 प्रतिशत डिस्सा लेते हैं। भादला सौर पार्क, जो 2,245 मेगावाट बिजली पैदा करता है, और एक अंधेरा सच छिपा है- बिजली कटौती, नए कठिनाइयों के लिए गरमारी, डिस्कॉम का भारी चाटा, उभोक्ताओं को महंगी बिजली की सलाई, किसानों के लिए रात में बिजली अपूर्णत की अमानवीय व्यवस्था, और सौर परियोजनाओं में व्यापक ग्रामीण इलाकों का आपान बाहरा सौर ऊर्जा ने राजस्थान को आपाननंद बनाने का सुनहरा सपना दिखाया है।

इसके जबाबदा में हार्वर्ड ने भी बिजली कटौती के विविधालय के प्रसारण के लिए एक अंधेरा सच छिपा है- बिजली कटौती, नए कठिनाइयों के लिए गरमारी, डिस्कॉम का भारी चाटा, उभोक्ताओं को महंगी बिजली की सलाई, किसानों के लिए रात में बिजली अपूर्णत की अमानवीय व्यवस्था, और सौर परियोजनाओं में व्यापक ग्रामीण इलाकों का आपान बाहरा सौर ऊर्जा ने राजस्थान को आपाननंद बनाने का सुनहरा सपना दिखाया है।

राज्य में सौर ऊर्जा क्षेत्र ने रोजगार सुजन में भी योगदान दिया है लेकिन वहाँ भी तकनीकी कुशल श्रमिकों को समृद्धिवाले अवसर नहीं है। 2025 तक, इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लगभग एक लाख नौकरियां पैदा हुई हैं लेकिन इसकी अधिकांश नौकरियां अस्थायी हैं। कुसुम योजना के तहत सौर पंखों की स्थापना और रखरखाव में स्थापित कठिनाइयों को काम मिला है, जबकि सौर पार्क के निर्माण में अक्षशल श्रमिकों को रोजगार मिला है लेकिन यहीं पर सौर पार्क में स्थानीय अराजक तत्वों के आतंक ने हालात खराब कर रखे हैं ऐसे एक परिवर्तित ने इस पीढ़ी को मुझ से सेवा करके बताया कि बाड़मेर, जैसलमेर में सौर ऊर्जा को पूरा जाता है। राजस्थान को आपान एक गंभीर समस्या आज भी बनी हुई है।

सौर पैनल आपूर्ति व स्थापना में गुणवत्ता जांच को अनिवार्य किया जाए। 2025 में राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सौर ऊर्जा वैनल आपूर्ति व स्थापना में गुणवत्ता जांच को अनिवार्य किया जाए। सिरमौर है, लेकिन यह चमक केवल सतही है। राजस्थान को सही मायनों में सौर ऊर्जा का गढ़ बनाना है, तो सरकार को अपनी नाकामियों से सबक लेना होगा। पारदर्शी, जन-केंद्रित नीतियां और भ्रष्टाचार पर सख्ती ही हस्त करो नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।

एक बिजली कटौती के लिए प्रशिक्षित तकनीशियों की जरूरत को पूरा करने में सरकार नाकाम हुई है। प्रशिक्षण केंद्रों की साथी और तकनीकी कौशल पर जोर न होने से यह क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहा। बिजली कटौती सौर ऊर्जान की एक पुरानी बीमारी है, जो 2025 में भी जनता को सता रही है। गर्मी के महीनों में, जब तापमान 48 डिग्री सेलिंसियस तक पहुंचता है, शहरी क्षेत्रों में 7-8 घंटे की अनियोजित कटौती का अमावास बात है। ऊर्जा दिन में तो बैटरी भंडारण की कमी इसे लेकिन यहीं पर सौर पार्क में स्थानीय अराजक तत्वों के आतंक ने हालात खराब कर रखे हैं ऐसे एक परिवर्तित ने इस पीढ़ी को मुझ से सेवा करके बताया कि बाड़मेर, जैसलमेर में सौर ऊर्जा को जाल देती है।

एक बिजली कटौती के लिए एक गंभीर समस्या आज भी बनी हुई है।

किसानों के लिए भारी बोझ है। कुसुम योजना के लिए प्रशिक्षित तकनीशियों की जरूरत को पूरा करने में सरकार नाकाम हुई है। प्रशिक्षण केंद्रों की साथी और तकनीकी कौशल पर जोर न होने से यह क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहा। बिजली कटौती सौर ऊर्जान की एक पुरानी बीमारी है, जो 2025 में भी जनता को सता रही है। गर्मी के महीनों में, जब तापमान 48 डिग्री सेलिंसियस तक पहुंचता है, शहरी क्षेत्रों में 7-8 घंटे की अनियोजित कटौती का अमावास बात है। ऊर्जा दिन में तो बैटरी भंडारण की कमी इसे लेकिन यहीं पर सौर पार्क में स्थानीय अराजक तत्वों के आतंक ने हालात खराब कर रखे हैं ऐसे एक परिवर्तित ने इस पीढ़ी को मुझ से सेवा करके बताया कि बाड़मेर, जैसलमेर में सौर ऊर्जा को जाल देती है।

एक बिजली कटौती के लिए एक गंभीर समस्या आज भी बनी हुई है।

किसानों के लिए भारी बोझ है। कुसुम योजना के लिए प्रशिक्षित तकनीशियों की जरूरत को पूरा करने में सरकार नाकाम हुई है। प्रशिक्षण केंद्रों की साथी और तकनीकी कौशल पर जोर न होने से यह क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहा। बिजली कटौती सौर ऊर्जान की एक पुरानी बीमारी है, जो 2025 में भी जनता को सता रही है। गर्मी के महीनों में, जब तापमान 48 डिग्री सेलिंसियस तक पहुंचता है, शहरी क्षेत्रों में 7-8 घंटे की अनियोजित कटौती का अमावास बात है। ऊर्जा दिन में तो बैटरी भंडारण की कमी इसे लेकिन यहीं पर सौर पार्क में स्थानीय अराजक तत्वों के आतंक ने हालात खराब कर रखे हैं ऐसे एक परिवर्तित ने इस पीढ़ी को मुझ से सेवा करके बताया कि बाड़मेर, जैसलमेर में सौर ऊर्जा को जाल देती है।

एक बिजली कटौती के लिए एक गंभीर समस्या आज भी बनी हुई है।

किसानों के लिए भारी बोझ है। कुसुम योजना के लिए प्रशिक्षित तकनीशियों की जरूरत को पूरा करने में सरकार नाकाम हुई है। प्रशिक्षण केंद्रों की साथी और तकनीकी कौशल पर जोर न होने से यह क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहा। बिजली कटौती सौर ऊर्जान की एक पुरानी बीमारी है, जो 2025 में भी जनता को सता रही है। गर्मी के महीनों में, जब तापमान 48 डिग्री सेलिंसियस तक पहुंचता है, शहरी क्षेत्रों में 7-8 घंटे की अनियोजित कटौती का अमावास बात है। ऊर्जा दिन में तो बैटरी भंडारण की कमी इसे लेकिन यहीं पर सौर पार्क में स्थानीय अराजक तत्वों के आतंक ने हालात खराब कर रखे हैं ऐसे एक परिवर्तित ने इस पीढ़ी को मुझ से सेवा करके बताया कि बाड़मेर, जैसलमेर में सौर ऊर्जा को जाल देती है।

एक बिजली कटौती के लिए एक गंभीर समस्या आज भी बनी हुई है।

किसानों के लिए भारी बोझ है। कुसुम योजना के लिए प्रशिक्षित तकनीशियों की जरूरत को पूरा करने में सरकार नाकाम हुई है। प्रशिक्षण केंद्रों की साथी और तकनीकी कौशल पर जोर न होने से यह क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहा। बिजली कटौती सौर ऊर्जान की एक पुरानी बीमारी है, जो 2025 में भी जनता को सता रही है। गर्मी के महीनों में, जब तापमान 48 डिग्री सेलिंसियस तक पहुंचता है, शहरी क्षेत्रों में 7-8 घंटे की अनियोजित कटौती का अमावास बात है। ऊर्जा दिन में तो बैटरी भंडारण की कमी इसे लेकिन यहीं पर सौर पार्क में स्थानीय अराजक तत्वों के आतंक ने हालात खराब कर रखे हैं ऐसे एक परिवर्तित ने इस पीढ़ी को मुझ से सेवा करके बताया कि बाड़मेर, जैसलमेर में सौर ऊर्जा को जाल देती है।

एक बिजली कटौती के लिए एक गंभीर समस्या आज भी बनी हुई है।

किसानों के लिए भारी बोझ है। कुसुम योजना के लिए प्रशिक्षित तकनीशियों की जरूरत को पूरा करने में सरकार नाकाम हुई है। प्रशिक्षण केंद्रों की साथी और तकनीकी कौशल पर जोर न होने से यह क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहा। बिजली कटौती सौर ऊर











# 'पहलगाम की छाया में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सतत निगरानी रखें'

**मुख्यमंत्री भजनलाल ने सभी संभागों व जिलों के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिये**

जयपुर, 23 अप्रैल। मुख्यमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते जिलों में भजनलाल शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी कहा कि सीमा पर तैनात सुरक्षा हमले के मद्देनजर प्रदेश में सभी जगह एजेंसियों के साथ निरंतर तालमेल मार्कूल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की बनाते हुए काम करें।

जाएं उन्होंने कहा, जिला अधिकारी और सूचना को बरतते हुए अपने जिलों में कानून-गम्भीरता से लिया जाए तथा तकाल

■ मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते जिलों में विशेष संजगता बरतने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ निरंतर तालमेल रखने के लिये कहा।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने सोशल मीडिया पर गहन निगरानी रखने तथा भ्रामक व अपतिजनक टिप्पणियों व अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिये।

व्यवस्था पर सतत निगरानी बनाए रखें। उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए।

शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर बौद्धियों का क्रॉसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त, पुलिस आयुक्त, जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करती जाए। साथ ही, सोशल मीडिया पर अन्य माध्यमों से सही सूचना



मुख्यमंत्री भजनलाल ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर, वीडियो क्रॉसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करती जाए। साथ ही, सोशल मीडिया पर अन्य माध्यमों से सही सूचना

एवं अन्य माध्यमों से सही सूचना

प्रसारित की जाए।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला निर्दीय एवं कायरतापूर्ण घटना है तथा इसके पूरा देश स्तरव्य है। इस घटना को श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता है, जिसकी बेहाली से और समय से पहले हत्या कर दी गई साथ ही शोक संतप्त विवरारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता है।

**पहलगाम के ...**

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किसी स्थानीय की मदद मिली थी। सूची के मुश्वाबिक, आतंकवादी विश्ववाद से कोरकरनाग हो गए हैं। वैसारं पहुंचने के लिए एक बायां निर्देश दिया गया है। इसका बहुत बाहर निवासी स्थानीय आतंकवादी या हैंडलर ने मदद की पुलिस ने कई स्थानीय लोगों से पृष्ठाताछ की है, लेकिन अब तक कोई औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पहलगाम हमले से एनडीएर सरकार के लिए प्रचार-प्रसार को बहुत नुकसान पहुंचा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने के 2019 के निर्णय के बाद रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना कर्मी शारीर में शांति पुनः कायम हो गई है।

पहलगाम हमले के अंतर्गत एक बायां निर्देश दिया गया है।

प्रथम पृष्ठ का शेष

**सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम पीड़ितों के लिये दो मिनट मौन रखा**

नवी दिल्ली, 23 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले पर बुधवार को दुख व्यक्त किया और इसकी कड़ी निंदा की। योर्स अदालत के न्यायालयीन वैठक की बैठक में सर्वसम्मान से आतंकवादी कृत्य के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जा सकता है जिससे भारत का कूटनीतिक गणित गढ़वाल सकता है।

साथ ही यह कदम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संघों की आलोचना के रूप में पेश करना होगा इसके लिए भारत को ना केवल कानूनी रूप से बल्कि नैतिक रूप से मजबूत केस बनाना होगा कि संधि से वे उद्देश्य प्राप्त कर्मों नहीं हो रहे, उनके लिए यह बार्ड गई थी।

आइ.डब्ल्यू.टी. को निर्मित करने के लिए यह कदम विश्व बैंक और उत्तराधीय संघों की आलोचना के रूप में पेश करना होगा इसके लिए भारत को ना केवल कानूनी रूप से बल्कि नैतिक रूप से मजबूत केस बनाना होगा कि संधि से वे उद्देश्य प्राप्त कर्मों नहीं हो रहे, उनके लिए यह बार्ड गई थी।

पाकिस्तान की कृत्यवाहनी व्यावहारिक अंदरूनी रूप से विश्व बैंक और यदि इस संधि की शर्तों को बदलने की धमकी का इसेमाल अकामपानी से किया जाए तो इसका दीर्घकालिक खतरों से भरा है और अगर इसमें सोच समझकर रखना नहीं बनाइ गई तो यह कदम नुकसान दे हो सकता है।

नाटकीय प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि धैर्य, इस्लामाबाद इसे अस्तित्व के लिए खतरा बाला सकता है, जिस पर तीव्र उद्देश्य दर्शाते हुए नहीं इसका बदलने की नीति को सावधानी से किया जाना चाहिए। भारत के पास ज्यादा प्रभावी तात्कालिक उपाय है।

लेकिन यह मनोवैज्ञानिक दबाव अनरोक्षत विवाद पैदा कर सकता है। जानकारी देगा। पी 5 देशों में चीन, फ्रांस, रूस, इंडिया तथा भ्रामक व अपतिजनक कायरतापूर्ण घटना देखने वाले जयपुर निवासी ने नोरज डिवानी के परिजनों से दूरभाष पर वार्ता कर संवेदनाएं व्यक्त की।

भारत के स्थानीय आतंकवादी विश्ववादी ने जानकारी देगा। पी 5 देशों में चीन, फ्रांस, रूस, इंडिया तथा भ्रामक व अपतिजनक कायरतापूर्ण घटना देखने वाले जयपुर निवासी ने नोरज डिवानी के परिजनों से दूरभाष पर वार्ता कर संवेदनाएं व्यक्त की।

पहलगाम हमले की अवधि अंत तक बायां निर्देश दिया गया है। इसके लिए एक बायां निर्देश दिया गया है। इसके लिए एक बायां निर्देश दिया गया है।

पहलगाम हमले के अंतर्गत एनडीएर सरकार के लिए प्रचार-प्रसार को बहुत नुकसान पहुंचा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने के 2019 के निर्णय के बाद रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना कर्मी शारीर में शांति पुनः कायम हो गई है।

पहलगाम हमले के अंतर्गत एनडीएर सरकार के लिए प्रचार-प्रसार को बहुत नुकसान पहुंचा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने के 2019 के निर्णय के बाद रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना कर्मी शारीर में शांति पुनः कायम हो गई है।

पहलगाम हमले के अंतर्गत एनडीएर सरकार के लिए प्रचार-प्रसार को बहुत नुकसान पहुंचा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने के 2019 के निर्णय के बाद रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना कर्मी शारीर में शांति पुनः कायम हो गई है।

पहलगाम हमले के अंतर्गत एनडीएर सरकार के लिए प्रचार-प्रसार को बहुत नुकसान पहुंचा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने के 2019 के निर्णय के बाद रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना कर्मी शारीर में शांति पुनः कायम हो गई है।

पहलगाम हमले के अंतर्गत एनडीएर सरकार के लिए प्रचार-प्रसार को बहुत नुकसान पहुंचा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने के 2019 के निर्णय के बाद रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना कर्मी शारीर में शांति पुनः कायम हो गई है।

पहलगाम हमले के अंतर्गत एनडीएर सरकार के लिए प्रचार-प्रसार को बहुत नुकसान पहुंचा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने के 2019 के निर्णय के बाद रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना कर्मी शारीर में शांति पुनः कायम हो गई है।

पहलगाम हमले के अंतर्गत एनडीएर सरकार के लिए प्रचार-प्रसार को बहुत नुकसान पहुंचा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने के 2019 के निर्णय के बाद रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना कर्मी शारीर में शांति पुनः कायम हो गई है।

पहलगाम हमले के अंतर्गत एनडीएर सरकार के लिए प्रचार-प्रसार को बहुत नुकसान पहुंचा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने के 2019 के निर्णय के बाद रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना कर्मी शारीर में शांति पुनः कायम हो गई है।

पहलगाम हमले के अंतर्गत एनडीएर सरकार के लिए प्रचार-प्रसार को बहुत नुकसान पहुंचा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने के 2019 के निर्णय के बाद रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना कर्मी शारीर में शांति पुनः कायम हो गई है।

पहलगाम हमले के अंतर्गत एनडीएर सरकार के लिए प्रचार-प्रसार को बहुत नुकसान पहुंचा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने के 2019 के निर्णय के बाद रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना कर्मी शारीर में शांति पुनः कायम हो गई है।

पहलगाम हमले के अंतर्गत एनडीएर सरकार के लिए प्रचार-प्रसार को बहुत नुकसान पहुंचा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने के 2019 के निर्णय के बाद रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना कर्मी शारीर में शांति पुनः कायम हो गई है।

पहलगाम हमले के अंतर्गत एनडीएर सरकार के लिए प्रचार-प्रसार को बहुत नुकसान पहुंचा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने के 2019 के निर्णय के बाद रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना कर्मी शारीर में शांति पुनः क